विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून 2010

महानगर : जलवायु परिवर्तन व उभरती चुनौतियाँ

-जन-संवाद-

आयोजक

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर

व

महानगर पर्यावरण सरंक्षण मंच, गोरखपुर

महानगर : जलवायु परिवर्तन व उभरती चुनौतियाँ

-जन-संवाद-

आयोजक

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर

व

महानगर पर्यावरण सरंक्षण मंच, गोरखपुर

महानगर : जलवायु परिवर्तन व उभरती चुनौतियां

-जन-संवाद-

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, स्थान : टाउनहाल, गोरखपुर

वैश्विक स्तर पर अनेक चर्चाओं का मुद्दा बना जलवायु परिवर्तन आज स्थानीय स्तर पर जाना पहचाना जाने लगा है। स्थानीय बहस–मुबाहिसों में प्रमुखता से स्थान पाये जलवायु परिवर्तन से कोई एक वर्ग या एक समुदाय नहीं प्रभावित है, वरन् इसने पूरे जीव–जगत को अपनी चपेट में लिया है। शोध बताते हैं कि पशु–पक्षियों, पेड़ – पौधों की अनेक ऐसी प्रजातियां, जो प्राकृतिक व पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होती थीं, विलुप्त हो चुकी हैं या फिर होने के कगार पर हैं। क्रमिक विकास और परिवर्तन दोनों ही एक – दूसरे के सहायक हैं। परिवर्तन तो सदियों से होता रहा है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ चीजें विलुप्त भी होती हैं, परन्तु परिवर्तन का यह संक्रमण काल है, जहां मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है, उसका अपना भविष्य मिटता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी चिन्ता लाज़मी है।

शहरी परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण स्थितियां और भी दुरूह होती जा रही हैं। सुविधा भोगी वर्ग शहरों में रहता है, लोग बेहतर जिन्दगी की तलाश में शहरों की ओर भागते हैं और जब यहां पर भी स्थितियां वैसी ही कष्टकारी हों, तो उनकी चिन्ता स्वाभाविक है। विगत वर्ष जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को गोरखपुर महानगर पर देखने की कोशिश के तहत् गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप द्वारा किये गये शोध ने शहर की जो तस्वीर प्रस्तुत की, वह निश्चित ही निराशाजनक एवं चिन्तनीय है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आम जन कही दुश्वारियां दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और आगे इनमें और भी वृद्धि होगी।

अतः लोगों को प्राप्त निष्कर्षों से परिचित कराने, समस्याओं के समाधान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 5 जून, 2010 को सायं 6:00 बजे से 8:00 बजे तक टाऊनहाल चौराहे पर ''महानगर : जलवायु परिवर्तन और उभरती चुनौतियां'' विषय पर एक जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में शहर के अनेक बुद्धिजीवी वर्गों – व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, राजनैतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के साथ–साथ पत्रकार वर्ग की भी खासी उपस्थिति रही।

उद्देश्य–

- **जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में महानगर की संवेदनशीलताओं से आम जनता को रूबरू कराना।**
- **गोरखपुर महानगर के विकास हेतु बने मास्टर प्लान की खामियों से लोगों को अवगत कराना।**
- **जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष महानगर की बढ़ती चुनौतियों से निपटने हेतु एक समेकित प्रयास व समग्र सोच को विकसित करना।**

कार्यशाला प्रारम्भ–

कार्यशाला का औपचारिक शुभारम्भ करते हुए गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप के अध्यक्ष डा0 शीराज़ अ0 वजीह ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस – 5 जून के अवसर पर विगत कई वर्षों से शहर की समस्याओं को संबोधित करते हुए रैली, गोष्ठी आदि होती रही है। परन्तु यह पहली बार है, जब शहर की समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में आये हैं। ये वे समस्याएं हैं, जिनका सामना हम और आप रोज करते हैं, पर उनसे निपटने के लिए आगे नहीं आते हैं। क्योंकि सभी दूसरे की बाट जोहते रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को संदर्भित करती हमारी अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, इस विषय पर आयोजित यह कार्यशाला दो सत्रों में विभाजित है।

महानगर में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन की समस्याएं

मंच संचालन एवं सूत्रधार : **डा0 मुमताज़ खान**

पैनल सदस्य :

डा0 एस0एस0 वर्मा, डा0 पी0के0 लाहिड़ी, श्री मोहन लाल गुप्ता, प्रो0 एस0सी0 त्रिपाठी, डा0 ईश्वर दास गुप्ता, डा0 एस0पी0 त्रिपाठी, श्री जे0के0 श्रीवास्तव, श्री विश्वमोहन तिवारी

सत्रारम्भ

अध्यक्ष जी0ई0ए0जी0 ने पैनल सदस्यों तथा वक्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि वैश्विक समस्या के तौर पर उभरे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गोरखपुर महानगर वासी भी अछूते नहीं हैं। शहर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समस्याएं और भी विकट हैं, क्योंकि गांव से शहर की तरफ रूख करने वाला व्यक्ति यदि आम सुख–सुविधाओं से वंचित हो तो शहर आधारित आजीविका के आधार पर अपने परिवार को सुखद व समृद्ध भविष्य देने का उसका सपना दम तोड़ने लगता है। विगत वर्ष में इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप द्वारा शोध किया गया, निष्कर्षतः महानगर में प्रमुख तीन समस्याएं निकल कर आयीं –

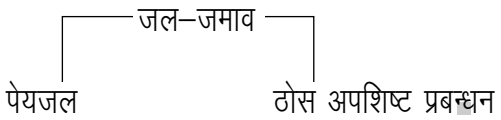

इनके कारणों को देखा जाये तो –

- महानगर में 18 प्रतिशत लोग नीची भूमि में रहते हैं। वर्षों पहले लोगों ने ये जमीनें कौड़ियों के मोल यह सोच कर खरीद ली कि आगामी दो–चार वर्षों में इसका स्तर अन्य स्थानों के बराबर होगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उल्टे नगर निगम के विकास कार्यों ने इन स्थानों को और भी नीचा किया।
- सार्वजनिक भूमि 21 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत ही रह गयी। लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण रिहायशी स्थानों की कमी के कारण लोगों ने सार्वजनिक भूमि को भी प्रशासन की मंजूरी से आवासीय स्थानों में बदलना प्रारम्भ किया।
- शहर में नये विकसित क्षेत्र जल–जमाव से अधिक प्रभावित होते हैं। लोगों ने इन्हीं में मकान बनाया। प्रशासन ने भी उसे मंजूरी दी, कि आगे कुछ वर्षों में यहां सारी सुविधाएं मुहैया हो जायेगीं, परन्तु अभी भी उन स्थानों पर पानी निकास की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पानी निकास के रास्ते एवं पानी एकत्रीकरण के स्रोत पाट कर घर बनाये जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घरों से निकलने वाले दैनिक प्रयोग के पानी का निस्तारण ही कठिन है। बारिश का पानी तो जमा होना ही है।
- शहर में ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है। पूरे शहर का मात्र 22 प्रतिशत क्षेत्र ही भूमिगत सीवेज व्यवस्था से आच्छादित है। वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। वर्ष 1950 के दशक में जब नगर निगम का प्रथम विस्तारीकरण एवं उसके द्वारा विकास कार्य कराये जा रहे थे, तभी भूमिगत सीवेज की व्यवस्था की गयी थी, तबसे लेकर आज तक उसकी पाइप लाइनें नहीं बदली गयीं। उनमें जगह–जगह से लीकेज हो रहा है, जिसके कारण बगल से जा रही पेयजल की पाइप लाइन भी प्रभावित होती है।
- बहुत से लोगों ने अपने घरों के गन्दे पानी व मल–मूत्र के निस्तारण हेतु निकले पाईप को जमीन में गहरे तक बोरिंग कराकर उससे जोड़ दिया है। यह गहराई लगभग 250 फीट या उससे अधिक होती है। ऐसी स्थिति में, आम तौर पर शुद्ध माने जाने वाले इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के पानी की शुद्धता कितनी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

- शहर में ठोस अपशिष्ट निस्तारण तो है, परन्तु उसके प्रबन्धन की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहता है, नालियां जाम होती हैं और फिर यहाँ जल–जमाव का एक प्रमुख कारण बनता है।

पिछले 10 वर्षों में हुई बारिश को आधार बनाकर किये गये शोध के निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि अगले 50 वर्षों में जुलाई–अगस्त–सितम्बर में अधिक बारिश होगी और तब महानगर में जल–जमाव की स्थितियां और दुरूह होगीं। जल–जमाव की अवधि बढ़ेगी और नये क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा। क्योंकि शहर की जल धारण क्षमता घट रही है। उल्लेखनीय है कि कभी शहर में 103 ताल–तलैये हुआ करते थे, आज मात्र 20 ही रह गये हैं।

दृष्टव्य है कि ये सभी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परन्तु जब इनके समाधान की बात आती है, तो अलग–अलग विभागों के अधिकार क्षेत्र की बात आने लगती है। पेयजल पाइप लाइन बिछाने व उसके रख–रखाव की जिम्मेदारी जल निगम की होगी, तो नालों की सफाई का काम नगर निगम के जिम्मे। जबकि इन विभागों में आपसी समन्वय बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम नागरिकों को भी आगे आना होगा।

मंच संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डा0 मुमताज खान ने कहा कि शहर की आपा–धापी में मुट्ठी भर लोग शहर भर की समस्याओं, चिन्ताओं को लेकर यहां एकत्र हुए हैं। निश्चित तौर पर चिन्ताएं बड़ी हैं। यदि हम 30 साल पूर्व के गोरखपुर को देखें तो उस समय यह शहर पूर्वांचल का 'सी' ग्रेड हिल स्टेशन हुआ करता था, जहां लोगों को पंखे की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी और आज हम एयर कण्डीशनर व कूलर के बगैर रह नहीं सकते। आने वाले भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा, इस बात की कल्पना वर्तमान स्थिति के आधार पर बखूबी की जा सकती है।

इस विषय पर अन्य उपस्थित लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

श्री जे0 के0 श्रीवास्तव, बैंक अधिकारी

जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ शब्दों की शक्ल में ही नहीं रह गया। इसे लोग महसूस भी करने लगे हैं। गर्मी के रिकार्ड टूटते जा रहे हैं, तो वर्षा पद्धति में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में पहले से ही संवेदनशील गोरखपुर और भी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। इसकी भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी है कि यहां पर केन्द्रीयकृत ड्रेनेज व्यवस्था को बनाये रखने में समस्या आती है। कई मुहल्लों मे तीन से चार माह तक जल–जमाव की स्थिति बने रहने के कारण वहाँ के छोटे–छोटे, दैनिक रोजगारों पर आधारित लोगों की आजीविका बेतरह प्रभावित होती है। आज का जो परिदृश्य है, उसके आधार पर वर्ष 2050 में जब शहर का विस्तार पिपराईच से पिपरौली तक होगा, तो शहर के ठोस अपशिष्टों का प्रबन्धन किस प्रकार किया जा सकेगा, यह अभी से चुनौती का विषय है।

डा0 एस0पी0 त्रिपाठी, पत्रकार

जलवायु परिवर्तन विश्व व्यापी समस्या है। हमने अपने भौतिक सुख व उत्थान के लिए अपने मूलभूत सहयोगियों जैसे – जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है। विकास के दौर में हमने अपने सुखद भविष्य को तलाशा व तराशा पर इसके दूरगामी परिणामस्वरूप आज हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है। आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए सुखद भविष्य तो दूर, सांस लेना भी दूभर हो जायेगा।

गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो यहां की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है। लगभग 30 वर्षों पहले गोरखपुर की आबादी 7000 थी और आज 7 लाख से ऊपर है, पर संसाधन नहीं बढे। परिणाम हमारे सामने है, आज उस अनुपात में हमारा शहर नित्यप्रति नयी–नयी समस्याओं से जूझ रहा है। कभी बिजली की कमी, तो कभी पानी का रोना, आवास की समस्या, तो कचरों का निस्तारण न होना, ये सभी आज गोरखपुर की नियति बन चुके हैं।

श्री मनोज, पी0जी0एस0एस0

शहर की अधिकांश समस्याओं के लिए नगर निगम जिम्मेदार है। गौरतलब है कि पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी का आयोजन नगर निगम के बगल में ही हो रहा है और उनका कोई प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित नहीं है। जनता की इन समस्याओं से इन अधिकारियों का कोई सरोकार न होना खुद ही एक बड़ी समस्या है।

श्री सुधाकर पति त्रिपाठी, नागरिक

शोध बताते हैं कि वर्ष 2050 तक इस धरती पर उपस्थित जीव–जन्तुओं की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी होगी। सच है कि लोप–विलोप का क्रम चलता रहता है। हमारे धार्मिक पुराणों में लोप विलोप का उल्लेख है। पुरातन समय में भी जीवों का लोप होता रहा है, जैसे डायनासोर का लुप्त होना, परन्तु वह क्रिया प्राकृतिक थी। जबकि आज जो क्रम है, वह मानवीय कारणों से है और इतनी अधिक तेजी से हो रहा है कि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा सिर्फ देहातों को ही नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। हम इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के जिस पानी को शुद्ध मानते थे आज वह भी शुद्ध नहीं है।

डा0 ईश्वर दास, व्यापार मण्डल प्रतिनिधि

पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से लगभग सभी लोग परिचित हैं, परन्तु उसके निवारण के विषय में किसी को कोई चिन्ता नहीं है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि पर्यारण प्रदूषण में उसकी भागीदारी नहीं है, फिर भी सच को स्वीकारना कोई नहीं चाहता है।

शहर तो समस्याओं से अटा पड़ा है और क्यों न हो, नियोजन 7000 लोगों पर जबकि उपभोगकर्त्ता 7 लाख लोग। अतः कहा जा सकता है कि यहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पेयजल एवं जल – जमाव के पीछे जनसंख्या वृद्धि भी एक मुख्य कारण है।

इसके साथ–साथ और भी कारक हैं, जो शहर को बदसूरत व बदहाल बनाते हैं। पेयजल के विषय में उल्लेखनीय है कि नगर निगम के पानी की पाइप सड़क के किनारे नालियों के सहारे जाती है। घर के अन्दर जाने वाले कनेक्शनों में रिसाव होता है। जब पानी बन्द होता है, तो पाइप नाली का पानी खींचता है, नालियों का गन्दा पानी एकत्र होता रहता है और पुनः आपूर्ति बहाल होने पर वही गन्दा पानी घरों में जाता है।

सुश्री प्रीती गुप्ता, नागरिक

विभिन्न संस्थानों, लोगों से बात करने पर निकला कि जल–जमाव का एक बड़ा कारण पॉलीथिन थैलियां हैं, जो नालियों को जाम करती हैं। ये न तो नष्ट होती हैं, न खत्म होती हैं। मिट्टी के अन्दर जाकर उसे भी

प्रदूषित कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज पॉलीथिन हमारे दैनिक जीवन में इतना रच–बस चुका है कि छोटे – छोटे पाउच से लेकर बड़ी–बड़ी थैलियां आदि सभी पालीथिन ही हैं, तो इस प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने का भी कोई समाधान होना चाहिए।

प्रो० एस०सी० त्रिपाठी,

अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, गो.वि.वि.गो.

शहर को समस्याओं का गढ़ बनाने, कूड़े के ढेर पर शहर को बिठाने के लिए बहुत हद तक हमारी सोच भी जिम्मेदार है। एक उदाहरण है – घर के कचरे को एक नियत स्थान पर एकत्र कर सफाई कर्मचारियों को दिया जा सकता है, पर नहीं। यह नहीं हो सकता। लोग पालीथिन थैली में कूड़ा भरकर सड़क पर या नालियों में फेंक देते हैं। यह एक बानगी है कि हम कितने संवेदनशील हैं, अपने शहर एवं उसकी समस्याओं के बारे में। शहर के जलस्रोतों पर अवैध कब्जा कर उनपर ईंट, पत्थरों का जंगल तैयार किया जा रहा है, तो पानी की व्यवस्था कहां होगी।

श्री मोहन लाल गुप्ता,

महानगर पर्यावरण संरक्षण मंच

शहर मुख्यतः जल–जमाव की समस्या से ग्रसित है। हल्की सी बरसात होते ही सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण है – जल के प्राकृतिक स्रोतों पर दबंगों, बाहुबलियों का अवैध ढंग से कब्जा। वर्ष 1951 के रिकार्ड के अनुसार शहर में ताल–पोखरों की संख्या 513 थी, परन्तु आज घटकर 17 ही रह गयी है।

जटाशंकर पोखरा कभी पूजा का एक बड़ा केन्द्र था, आज एक अहाते के अन्दर सिमट गया है। सावित्री रिसर्च सेण्टर भी एक ताल के ऊपर खड़ा है।

प्रो० एस० एस० वर्मा, रजिस्ट्रार

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर की उत्पत्ति, विकास, विस्तार एवं समस्याओं पर लगातार काम चलता रहता है। इस विषय में अनेक शोध हुए हैं और हो भी रहे हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि गोरखपुर महानगर में जिस अनुपात में जनसंख्या का विस्तार हुआ, उस अनुपात में सुविधाएं नही बढ़ीं। ध्यातव्य है कि गोरखपुर महानगर राप्ती व रोहिन के संगम पर बसा हुआ है। प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार पश्चिम का ढाल पश्चिम की तरफ व पूरब का ढाल पूरब की तरफ था, जिसके अनुसार पश्चिम तरफ आवासीय विस्तार कम होने तथा निचले क्षेत्र अधिक होने के कारण पानी फैल कर निकल जाता था, जबकि पूरब का पानी तालों व नालों के रास्ते रामगढ़ ताल और फिर वहां से गोर्रा होते हुए राप्ती नदी में चला जाता है। विकास व विस्तार के क्रम में पश्चिम में जल निकास की कोई प्राकृतिक व्यवस्था न होने के कारण वहां जमा जल को पम्प के द्वारा निकाला जाता है, जबकि पूरब की व्यवस्था वही थी। पर वर्तमान में दिनोंदिन जल–जमाव के नये क्षेत्र तैयार हो रहे हैं, जल–जमाव की अवधि बढ़ रही है और आम आदमी परेशान हो रहा है। इसमें प्रशासन के साथ–साथ नागरिक भी अहम् भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जल संग्रहण स्रोतों को तो हम ही ने प्रशासन की मूक सहमति से खत्म किया है।

श्री पी०के० लाहिड़ी,

महानगर पर्यावरण संरक्षण मंच

गोरखपुर महानगर एक तरफ तो जल–जमाव की समस्या से प्रभावित है, तो दूसरी तरफ शहर में कूड़ा–करकट का उचित प्रबन्धन न होना भी हमारी समस्या में गुणात्मक वृद्धि कर रहा है। प्लाटिक का बढ़ता प्रयोग एवं बेतरतीब निस्तारण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में समस्याओं से निपटने के लिए हम नागरिक समुदाय को ही आगे आना होगा।

समाधान "संवेदनशीलता से निपटने में सहायक संस्थाएं"

समस्याएं गोरखपुर शहर की हैं, तो उससे निपटने के लिए शहरवासियों को ही आगे आना होगा। कुम्भकर्णी नींद सो रहे विभागों व प्रशासन को जगाने की जिम्मेदारी आमजन पर ही है। इस सन्दर्भ में सुविज्ञ वक्ताओं द्वारा समाधान के कुछ उपाय भी सुझाये गये, जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है –

- समय–समय पर शहर ने समस्याओं के मकड़जाल से अपने–आप को मुक्त कराने के लिए जनान्दोलन किया है। इस समय भी उसी प्रकार के आन्दोलन की आवश्यकता है, जिसमें जनता के बीच से विभिन्न वर्गों के साथ सभी सम्बन्धित विभागों को एक मंच पर आना होगा। समस्याओं के निराकरण हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी अभिकरणों को एक साथ मिलकर समन्वित योजना बनानी होगी।
- शहर के लिए प्रशासन की मृतप्राय संवेदना को जगाने हेतु एडवोकेसी करनी होगा। राजनीतिक पार्टियों को इस आन्दोलन के साथ जोड़ना एक सशक्त कदम होगा।
- नौकरशाहों के भरोसे शहर का नियोजन नहीं छोड़ा जा सकता है। शहर की समस्या को शहरवासी झेलते हैं। अतः नियोजन में भी जनता को भागीदार बनना होगा। क्रियान्वयन की उचित मानिटरिंग करनी होगी।
- विकास की दीर्घकालिक योजना बननी चाहिए। तभी समय रहते यथोचित परिणाम सामने आ सकते हैं।

जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं। उन्हें अंदेशा है कि अगले 1000 वर्षों बाद हमारे पास भूगर्भ जल नहीं होगा, तो हम समुद्र का पानी किस प्रकार पीने लायक बना सकते हैं और इस पर उन्होंने अभी से माथा–पच्ची करनी प्रारम्भ कर दी है।

- हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, पर उसका प्रबन्धन न होने के कारण आने वाले दिनों में पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है। शहर के ताल–तलैयों के खत्म होने से पानी प्रबन्धन के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बारिश के पानी के संग्रहण व संरक्षण हेतु व्यक्तिगत स्तर पर किये गये प्रयास भी सार्थक हो सकते हैं।
- इस तथ्य को समझना होगा कि प्रशासन और जनता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः हमें अपना दायित्व समझते हुए स्वयं के व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। हम पॉलीथिन का प्रयोग कम से कम करें। घर से निकलने वाले कूड़े को घर पर ही अलग–अलग करके रखें और इनका निष्पादन सही स्थान पर करने में प्रशासन का सहयोग करें।
- हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। प्रत्येक मुहल्ले में पर्यावरण संरक्षण मंच के दो–तीन स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाना चाहिए। जिनका मुख्य कार्य मुहल्ले में पर्यावरण सम्बन्धी गतिविधियों की मानिटरिंग करना हो। उनका यह भी काम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पर्यावरण विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाये, उसका नाम अखबारों में प्रकाशित कर उसे सार्वजनिक रुप से लज्जा का पात्र बनाया जाय।
- पॉलीथिन बैग की जगह पर झोला लेकर चलने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ उपहार दिये जाने की योजना भी चलाई जा सकती है।

- ठोस अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु नागरिक पहल करनी होगी। **पुर्दिलपुर मुहल्ले में 206 घरों के लोग मिलकर अपने यहां ठोस अपशिष्टों का प्रबन्धन स्वयं कर रहे है। इसके लिए उन्होंने आपसी सहमति व योगदान से दो सफाई कर्मियों को नियुक्त किया है, जो घरों से कूड़ा एकत्र करते हैं। कुछ कचरे ऐसे होते हैं, जिनसे खाद बनाई जा सकती है, जैसे सब्जी, फलों के छिलके आदि। उनको एकत्र कर खाद बनाने के लिए एम0जी0पी0जी कालेज में एक टैंक बनाया गया है, जबकि कुछ कचरे ऐसे हैं, जो पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनः प्रयोग में लाये जा सकते हैं, इन्हें कबाड़ियों को दिया जाता है।** तो क्या अन्य मुहल्लों में इसे उदाहरण बनाते हुए कार्य नहीं शुरू किया जा सकता है।

डा0 सैयद जमाल अहमद, कांग्रेस पार्टी

नागपुर में शहर की सफाई व्यवस्था नागरिकों के जिम्मे है। वे ही उसका नियोजन करते हैं एवं कार्य की मानिटरिंग भी करते हैं। तो क्या हम इस उदाहरण को नहीं अपना सकते हैं। गोरखपुर की पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश के साथ वार्ता कर समाधान हेतु प्रयास करना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और राजनैतिक पार्टी से जुड़ा होने के कारण मैं इस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

माध्यम और भी हैं . . .

गीत, संगीत एक ऐसा माध्यम है, जिसे पूरी दुनिया में लोग रूचि के साथ सुनते हैं और इसके माध्यम से कही गयी बातें, लोगों के जेहन में अवश्य रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आई–नेक्स्ट की तरफ से डी–7 बैण्ड ग्रुप के श्री प्रतीक सरन ने पर्यावरण सम्बन्धी निम्न गीत प्रस्तुत किया। गिटार व ड्रम पर उनका साथ क्रमशः श्री मोहित कुमार शर्मा व श्री सोमनाथ चक्रवर्ती दे रहे थे।

''आज करेंगें हम वादा दुनिया के नाम एक वादा।
तोड़ा जो हमने खुद का आशियां, आज हम बसायें फिर वो आशियां ।।
यू मैनेजिंग अ पार्ट
सावन आया करता था, लेकर खुशियों की बूंदे।
अब दे जाता है ना जाने क्यूं इन आंखों में बूंदे।।
व्यक्ति के हाथों मे थे मिट्टी के खिलौने, अब तब हैं क्यों इन हाथों में बारूद के गोले।।
खुशनुमा सुबह थी क्यों खो दिया
खुशियों की बगिया थी क्यों खो दिया,
मीठी सी नदिया थी क्यों खो दिया, सोने सी जमीन थी क्यों खो दिया।
यू मैनेजिंग अ पार्ट
आज हम पूरा करें हर एक वादा, दुनिया के नाम का हर एक वादा।
तोड़ा जो हमने खुद का आशियां, आज हम बसायें फिर वो आशियां।।

''प्रशासन से कुछ अपेक्षाएं''

मंच द्वय की तरफ से जनता व प्रशासन के समक्ष कुछ मांगें रखी गयीं –

- ☞ हमारी मांग है कि विकेन्द्रित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाये।
- ☞ शहर के कटोरेनुमा शक्ल की दुहाई देकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ना बन्द करे। हमारी मांग है कि प्रशासन द्वारा एक तटस्थ विकेन्द्रित ड्रेनेज व्यवस्था लागू की जाये।
- ☞ हमारी मांग है कि गोरखपुर महानगर में जितने भी ऑटोरिक्शा हैं, उन्हें सी0एन0जी0 से जोड़ा जाये। इसकी व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से प्रशासन द्वारा लागू की जाये।
- ☞ हमारी मांग है कि जनता आगे आये। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वो अन्य लोगों को जागरूक करे।
- ☞ हमारी मांग है कि शहर में वर्षा जल संग्रहण को आवश्यक बना दिया जाये। शहर की जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा जल संभरण व्यवस्था जरूर लागू की जानी चाहिए। जिससे पानी सड़कों पर न फैलकर भूगर्भ में जाये।

धन्यवाद ज्ञापन

गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप के संयुक्त सचिव श्री सुमन सिन्हा ने सभी आगन्तुकों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि मूलभूत प्रश्न यह है कि ताल–तलैयों की संख्या घटी क्यों? क्योंकि उनका रख–रखाव सही नहीं था, उनकी हदबन्दी नहीं की गयी थी, वे इस लायक नहीं थे, कि कोई वहां पर जाकर थोड़ी देर बैठ पाता, तो ऐसी स्थिति में आम नागरिक का जुड़ाव उन स्थानों से कैसे हो सकता था। यदि उनकी हदबन्दी की गयी होती, तो वे निश्चित ही समाप्त नहीं होते। इतिहास की गलतियों से सबक लेकर जो 17 तालाब बचे हैं, उनका प्रबन्धन व हदबन्दी यदि शासन प्रशासन ने नहीं किया तो जल्द ही वे भी विलुप्त तालों की संख्या बढ़ायेगें।

अतः प्रशासन से एक आवश्यक मांग यह भी है कि जिन्दा बचे तालाबों को जीवित रखने की प्रक्रिया में तेजी लायें, ताकि महानगर की जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष होने वाली चिन्ताओं में कमी आ सके।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास व पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रही है। संस्था शुरूआत से ही लघु सीमान्त किसानों, उनकी कृषि एवं आजीविका से जुड़े सवालों पर प्रमुखता से केन्द्रित रही है।
जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को शहरी संदर्भ में देखने के दौरान संस्था ने महानगरीय क्षेत्र में ऐसी चुनौतियों को देखा, जो आगामी वर्षों में महानगरीय जीवन पद्धति को और जटिल बनाने वाली हैं, बशर्ते अभी ही उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो।
प्रस्तुत रिपोर्ट महानगर की उन्हीं समस्याओं को संदर्भित व सम्बोधित करती जनसभा की है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर-273001
फोन : 0551-2230004 फैक्स : 0551-2230005
ई-मेल : geag2@sancharnet.in, geag_india@yahoo.com
वेबसाइट : www.geagindia.org